पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राकेश सिंह

बनाम

बिहार राज्य

2016 का आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 1215

27 जून 2025

[माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव]

विचार के लिए मुद्दा

क्या मृतक की चाकू से हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि, हथियार की बरामदगी के अभाव, जांच अधिकारी की जांच न होने तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में मामूली विसंगतियों की उपस्थिति में कानूनी रूप से टिकने योग्य थी।

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता - धारा 302 - हत्या - प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही - चिकित्सा पुष्टि - मामूली विरोधाभास

मृतक के पिता और भाई तथा स्वतंत्र गवाह के प्रत्यक्षदर्शी बयानों पर आधारित अभियोजन पक्ष का मामला - चिकित्सा निष्कर्षों द्वारा समर्थित साक्ष्य जो धारदार हथियार से छाती पर घातक चोट दर्शाते हैं - मामूली विसंगतियां और प्रथम सुचना प्रतिवेदन में देरी महत्वहीन है।

माना गया: दोषसिद्धि कायम है; प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सा साक्ष्य सुसंगत हैं। [पैरा 26-30]

आपराधिक कानून - जांच अधिकारी की जांच न करना - प्रभाव

हालांकि जांच अधिकारी की जांच नहीं की गई, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा कोई पूर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं किया गया - अन्य गवाह सुसंगत और भरोसेमंद थे - केवल जांच अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण दोषसिद्धि प्रभावित नहीं हुई। **निर्णय:** जांच अधिकारी की जांच न करना पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति में घातक नहीं है। [पैरा 30]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 134 – गवाहों की संख्या – एकमात्र विश्वसनीय गवाही की पर्याप्तता

न्यायालय ने दोहराया कि साक्ष्य की गुणवत्ता मायने रखती है, मात्रा नहीं – दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए एक गवाह का भी विश्वसनीय साक्ष्य पर्याप्त है।

निर्णय: सुसंगत और सुसंगत गवाही के बल पर दोषसिद्धि वैध है। [पैरा 29]

भारतीय दंड संहिता - धारा 302 बनाम 304 भाग II - धारा 300 का अपवाद 4 - प्रयोज्यता - पूर्वचिंतन और क्रूरता

निहत्थे पीड़ित पर आरोपी द्वारा धारदार हथियार से बार-बार वार करना - कोई गंभीर या अचानक उकसावे की स्थिति नहीं - क्रूर और जानबूझकर किया गया कार्य; धारा 300 का अपवाद 4 लागू नहीं होता। **निर्णय:** धारा 302 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई; अपवाद 4 को बाहर रखा गया। [पैरा 33-35]

साक्ष्य की प्रशंसा – विरोधाभास – देरी – उद्देश्य – प्रतिकूल गवाह

कुछ गवाहों की गैर-परीक्षा और अन्य की प्रतिकूलता मामले को ध्वस्त नहीं करती है – मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाह सुसंगत हैं और चिकित्सा साक्ष्य

द्वारा पुष्टि की गई है – प्रथम सुचना प्रतिवेदन में देरी की व्याख्या की गई है और उद्देश्य मौजूद है।

निर्णय: विचारण न्यायालय का आकलन उचित है; दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। [पैरा 27-32]

न्याय दृष्टान्त

रम्मी बनाम मध्यप्रदेश राज्य, **(1999) 8** एससीसी **649** – छोटी-मोटी विसंगतियां महत्वहीन – पर भरोसा किया गया; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर, **(2010) 12** एससीसी **324** – गवाहों की विश्वसनीयता – का पालन किया गया; भागचंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य , **(2021) 18** एससीसी **274** – मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि – लागू; सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य, एआईआर **1983** एससी **484** – मौखिक बनाम चिकित्सा साक्ष्य – लागू; अमर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी), **(2020) 19** एससीसी **165** - एकल गवाही का मूल्य - पर भरोसा किया गया; दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर **1953** एससी **364** – करीबी रिश्तेदारों की गवाही – का पालन किया गया; बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, **(1996) 2** एससीसी **317** – आईओ द्वारा गैर-परीक्षा घातक नहीं है – इस पर भरोसा किया गया; बाबू बनाम तमिलनाडु राज्य, **(2013) 4** एससीसी **448** – धारा 300 का अपवाद 4 – क्रूर मामलों में लागू नहीं – लागू; भगवान मुंजाजी पावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(1978) 3** एससीसी **330** – अचानक लड़ाई और पूर्वचिंतन – लागू; कुन्हिमुहम्मद बनाम केरल राज्य, **2024** एससीसी ऑनलाइन एससी **3618** – अनुचित लाभ और क्रूरता के सिद्धांत को दोहराया गया – लागू किया गया

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, **1860** – धारा 302, 304 भाग II, धारा 300 अपवाद 4; दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** – धारा 164, 313, 374; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, **1872** – धारा 134, 3

मुख्य शब्दों की सूची

खंजर से हमला, प्रत्यक्षदर्शी गवाह, मेडिकल पुष्टिकरण, जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा, प्रतिकूल गवाह, धारा 302 आईपीसी, अचानक झगड़ा, धारा 300 के लिए अपवाद 4, साक्ष्य की गुणवत्ता बनाम मात्रा, पोस्टमार्टम चोटें, पूर्वचिंतन, प्रथम सुचना प्रतिवेदन में देरी, मामूली विरोधाभास।

प्रकरण से उत्पन्न

छपरा से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या **66/1997** में दिनांक **20.09.2016** को दोषसिद्धि का निर्णय और दिनांक **26.09.2016** को सजा का आदेश पारित किया गया मुफस्सिल पीएस केस संख्या **191/1995**, जिसमें अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री संजीव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री नरेंद्र कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 1215

थाना कांड सं.-191 वर्ष 1995 थाना- छपरा मुफ्फसिल जिला-सारण से बाहर उत्पन्न

==========

राकेश सिंह, पुत्र- राम प्रवेश सिंह, निवासी गमहरिया, थाना- जलालपुर, जिला-छपरा, सारण (बिहार)।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः-

अपीलार्थी के लिए : श्री संजीव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री नरेंद्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, ए.पी.पी (अ.लो.अभि)

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव

सी.ए.भी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूति श्री मोहित कुमार शाह)

तारीखः 27.06.2025

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे "द.प्र.सं." कहा जाएगा) की धारा 374 (2) के तहत वर्तमान अपील, द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा (जिसे आगे "विद्वान विचारण न्यायाधीश" कहा जाएगा) के विद्वान न्यायालय द्वारा 1997 के सत्र विचारण सं. 66 में (1995 के छपरा मुफस्सिल थाना मामले सं. 191 से उत्पन्न) में क्रमशः

दिनांक 20.09.2016 और 26.09.2016 को पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ पेश की गई है। दिनांक 20.09.2016 के उक्त दोषसिद्धि निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे "भा.द.सं." कहा जाएगा) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और ऐसा न करने पर, अपीलकर्ता को एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.07.1995 प्रातः 02:00 बजे, सूचना देने वाले सुरेंद्र प्रसाद साह के फर्द बयान को जलालपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक श्री जी.एस. चौबे द्वारा दर्ज किया गया था। अपने *फर्दबयान* में, सुरेंद्र प्रसाद साह (इसके बाद यहां "सूचना देने वाले" के रूप में संदर्भित) ने कहा है कि 08.07.1995, दिन-शनिवार, लगभग 06:00 बजे शाम को अशोक सिंह, मनोज सिंह और राकेश सिंह (अपीलकर्ता) सुचक की पान की दुकान पर पहुंचे और दुकान में लटकाए गए तिरंगे *(गुटका)* को तोड़ दिया, जिस पर सुचक के बड़े भाई राम मंगल प्रसाद (मृतक) ने आपत्ति जताई, जिस पर अशोक सिंह ने मृतक को दुकान से बाहर निकालने और उसे जान से मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद मनोज सिंह और राकेश सिंह (अपीलकर्ता) ने सुचक के बड़े भाई को पकड़ लिया था और उसे दुकान के अंदर से बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था उसने उनसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे की। सुचक ने आगे कहा है कि मनोज सिंह ने तब उसके भाई को पीछे से पकड़ लिया था और फिर राकेश सिंह (अपीलकर्ता) ने अपनी जेब से एक खंजर निकाला था और उसके भाई के सीने पर खंजर से वार किया था। उसके बाद राकेश सिंह ने उसके भाई

की छाती पर दूसरा खंजर मारा और फिर से चाकू घुमाया, जिसके बाद सुचक ने शोर मचाया और जब वह दुकान से बाहर आया तो उसने देखा कि सह-ग्रामीण राम दयाल चौधरी (पीडब्लू-7/ अ.सा.7), मोती चंद साह (पीडब्लू-1/ अ.सा.1), हुलास राम (पीडब्लू-4/ अ.सा.4) और दीन दयाल राम (पीडब्लू-2/ अ.सा.2) वहाँ पहुँच गए थे, जो पास में ही मौजूद थे। इसके बाद, सभी आरोपी व्यक्तियों ने सुचक के भाई को दुकान के सामने जमीन पर धकेल दिया था और उन पर हमला करने के लिए उनका पीछा भी किया था, जिसके बाद वे भागने लगे थे, हालांकि कई सह-ग्रामीण वहां पहुंच गए थे, जिससे आरोपी व्यक्ति भाग गए थे। सुचक द्वारा आगे कहा गया है कि उसने तब अपने भाई को खून से लथपथ देखा और वह दर्द से छटपटा रहा था और बहुत खून बह जाने के कारण तुरंत उसकी मृत्यु हो गई थी। सुचक ने आगे कहा है कि उसका विश्वास है कि आरोपी व्यक्तियों ने उसके भाई की हत्या करने के इरादे से उसे दुकान से बाहर निकाला था और उसकी छाती पर खंजर से वार किया था। सूचना देने वाले ने *फरदबेयान* पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था और जिसे उसने दिलीप कुमार नामक एक गवाह की उपस्थिति में समझ लिया था, जिसने भी उक्त *फर्दबयान* पर हस्ताक्षर किए थे।

3. सूचना देने वाले के उक्त *फरदबेयान* के आधार पर, एक अशोक सिंह, मनोज सिंह और राकेश सिंह (अपीलार्थी) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत 1995 के छपरा मुफ्फसिल थाना मामला सं. 191 वाली औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन 09.07.1995 को 11:30 ए. एम. (पूर्वाह्न) बजे दर्ज की गई थी जाँच के बाद और अपीलार्थी और एक मनोज सिंह के मामले को सही पाए जाने के बाद, पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता

की धारा 302/34 के तहत 07.02.1996 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, अशोक सिंह को मुकदमे में (परीक्षण) के लिए नहीं भेजा गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने तब मनोज सिंह और राकेश सिंह (अपीलार्थी) के खिलाफ दिनांक 19.02.1996 के आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया था, हालांकि, अशोक सिंह से संबंधित अंतिम फॉर्म को स्वीकार कर लिया गया था। यह मामला 28.01.1997 को सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, जिसके बाद इसे 1997 के सत्र विचारण सत्र परीक्षणसंख्या 66 के रूप में गिना गया था।विद्वत विचारण न्यायालय ने तब मनोज सिंह और राकेश सिंह (अपीलार्थी) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दिनांक 08.06.2001 को आरोप तय किए थे, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

4. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की थी। पीडब्लू-1/ अ.सा.1 मोती चंद साह, पीडब्लू-2/अ.सा.2 दीन दयाल राम, पीडब्लू-4/ अ.सा.4 हुलास राम, पीडब्लू-5/ अ.सा.5 रुदल सिंह और पीडब्लू-8/ अ.सा.8 धर्मनाथ मांझी हालांकि स्वतंत्र गवाह हैं, लेकिन उन्हें शत्रुतापूर्ण (पक्षद्रोही) घोषित किया गया है। पीडब्लू-3/ अ.सा. 3 सुदर्शन साह, पीडब्लू-6/ अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह (सुचक) और पीडब्लू-7/ अ.सा. 7 राम दयाल चौधरी को चश्मदीद गवाह बताया गया है। पीडब्लू-9/ अ.सा.9 डॉ. राम इकबाल प्रसाद डॉक्टर हैं, जिन्होंने मृतक-राम मंगल प्रसाद के शव का पोस्टमार्टम (परीक्षण) किया था, जबकि पीडब्लू-10/ अ.सा.10 सुरेश कुमार और पीडब्लू-11/अ.सा.11 श्रवण कुमार सिंह अधिवक्ता क्लर्क हैं, जिन्होंने औपचारिक प्राथमिकी, अन्वीक्षा जांच रिपोर्ट और खून से लथपथ मिट्टी की जब्ती सूची को साबित किया है जैसा कि केस-डायरी में दर्शाया गया है।

5. श्री संजीव कुमार मिश्रा, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री नरेंद्र कुमार, अधिवक्ता की सहायता से प्रस्तुत किया है कि मुकदमे के दौरान प्रदर्शित दस्तावेज मूल होने चाहिए, हालांकि वर्तमान मामले में केवल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी प्रदर्शित की गई है, इसलिए इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले का संदर्भ दिया गया है। ***सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली),*** रिपोर्ट (2010) 6 एस. सी. सी. 1, पैराग्राफ सं. 170 से 172 तक जिनका पुनरुत्पादन यहां नीचे किया गया हैः-

> *"170. राज्य द्वारा यह बताया गया कि रूप सिंह की उक्त रिपोर्ट कानूनी रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह एक फोटोकॉपी है और इसलिए, संहिता की धारा 293 के संदर्भ में रिपोर्ट के दायरे में नहीं आती है।दूसरे शब्दों में, साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में जब तक मूल दस्तावेज को अदालत की जांच के लिए नहीं रखा जाता है, तब तक इस संबंध में उचित द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व किए बिना फोटोकॉपी पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। किसी भी मामले में, संहिता की धारा 293 और धारा 294 दोनों जो कुछ परिस्थितियों में दस्तावेजों के औपचारिक प्रमाण के साथ वितरित करती हैं, यह स्पष्ट करती हैं कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना चाहिए, वे मूल होने चाहिए।*
>
> *171. तर्क के लिए मानते हुए, हालांकि स्वीकार नहीं करते हुए, कि रूप सिंह की उक्त रिपोर्ट यानी एक्स. एक्स. (प्रदर्श) पीडब्लू 89/ अ.सा. 89 डीबी स्वीकार्य है, भले ही एक फोटोकॉपी रिकॉर्ड में रखी*

गई हो और भले ही कहीं भी यह सबूत नहीं आया है कि उसी की तुलना की गई है और अदालत द्वारा मूल के साथ जांच की गई है और फिर रिकॉर्ड में रखी गई है, फिर भी यह इस तथ्य के आलोक में सभी विश्वसनीयता खो देता है कि अग्रेषण पत्र और रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त दस्तावेजों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है क्योंकि अग्रेषण पत्र और रिपोर्ट के बीच पार्सल की संख्या के क्रम को किसी ने बदल दिया है जो तथ्य अस्पष्ट है। इसलिए, उक्त रिपोर्ट की वास्तविकता पर और संदेह पैदा करता है। प्रश्न 3 के संबंध में रिपोर्ट से ही पता चलता है कि "ऐसा प्रतीत होता है कि दो कार्ट्रिज केस सी-1 और सी-2 को दो अलग-अलग हथियारों से दागा गया है।"विशेषज्ञ की यह राय अस्पष्ट थी और उक्त राय के आधार पर बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य को कोई विश्वास नहीं दिया जा सकता है कि दो व्यक्ति थे जिन्होंने दो अलग-अलग हथियारों से दो अलग-अलग शॉट दागे थे।इसके अलावा, उक्त रिपोर्ट अग्रेषण पत्र के प्रश्न 7 पर विचित्र रूप से मौन है जिसमें विशेष रूप से जीवित कार्ट्रिज पर विभिन्न निशान और गोली खाली होने के बारे में पूछा गया था।

172. बचाव पक्ष का यह रुख कि यह मत व्यक्त करने के लिए कि दो कारतुस के मामले एक ही हथियार से हैं या नहीं, पिस्तौल की आवश्यकता नहीं है, और पिस्तौल की आवश्यकता केवल तभी होती है जब राय मांगी जाती है कि वे उस विशेष हथियार से हैं या नहीं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कार्ट्रिज केस के अंदर दबाव बनाया जाता है,

जिसके परिणामस्वरूप गोली को बैरल से बाहर धकेल दिया जाता है, तो निशान में इस हद तक अंतर होता है कि यह या तो स्पष्ट या अस्पष्ट और चपटा या गहरा हो सकता है, इसलिए अपराध और परीक्षण फायरिंग के हथियार के अभाव में इस असमानता के कारण कोई राय नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा एक बार जब रूप सिंह की रिपोर्ट को अस्वीकार्य बना दिया जाता है तो बचाव पक्ष के दो बंदूक सिद्धांत पूरी तरह से अस्वीकार्य हो जाते हैं और जो बचा रहता है वह यह है कि मौके पर पाए गए दो खाली हैं।.22" बोर कारतुस, कि टाटा सफारी में पाई गई जीवित गोली एक है। .22" कारतूस और यह कि अपीलार्थी की बंदूक एक है। .22" बोर पिस्तौल जिसका उपयोग जेसिका लाल की हत्या के अपराध के लिए किया गया था।"

6. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि धारा 164 दंड प्रकिया संहिता के तहत गवाहों द्वारा दिए गए बयान को अपीलार्थी को कथित अपराधों का दोषी ठहराने के उद्देश्य से नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हुआ है और बचाव पक्ष के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है।इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि गवाहों का साक्ष्य, में गंभीर विरोधाभास हैं। विशेष रूप से स्वतंत्र गवाह, यानी पीडब्लू-7/ अ.सा. 7 राम दयाल चौधरी, जांच अधिकारी की जांच महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ सं.2 का संदर्भ दिया गया है। पीडब्लू-7/ अ.सा.7 के साक्ष्य में से यह प्रस्तुत करने के लिए कि पीडब्लू-7/ अ.सा.7 ने उसमें गवाही दी है कि उसने देखा था कि एक दुकानदार को मार दिया गया था।उसने यह भी कहा है कि

आरोपी ने गोली चलाई थी और भाग गया था, इसके अलावा यह कहते हुए कि छाती पर खंजर से हमला किया गया था और राकेश सिंह ने हमला किया था और भाग गया था।पैराग्राफसं. 4 का भी संदर्भ दिया गया है। पीडब्लू-7/ अ.सा.7 के बयान में कहा गया है कि पीडब्लू-7/अ.सा.7 ने उसमें कहा है कि 100 लोग वहां मौजूद थे क्योंकि विचाराधीन दुकान एक बाजार में स्थित थी।पैराग्राफ सं.5 का अगला संदर्भ दिया गया है। पीडब्लू-7/अ.सा.7 के बयान में कहा गया है कि जिस समय मृतक की हत्या हुई थी, उस समय उसके परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। पैराग्राफ सं. 38 पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। पीडब्लू-6/ अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह (सुचक) के बयान में कहा गया है कि उसने उसमें कहा है कि घटना के समय, उस पर हमला नहीं किया गया था और झगड़े को तारकेश्वर साह, दिलीप कुमार, राज किशोर और अशोक चौधरी ने अलग कर दिया था, हालांकि उक्त व्यक्तियों में से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर स्वतंत्र गवाहों को रोक दिया है। मामले के वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों को दबाने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच के लिए भौतिक गवाहों को लाना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है, हालांकि वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी को भी रोक दिया गया है और पूरे साक्ष्य से पता चलेगा कि यह विसंगति और संदेह से भरा है।इस संबंध में, विद्वत खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है। ***राजेन्द्र यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य,*** 1998 में सूचित (2) पी.एल.जे.आर. 434 में रिर्पोट किया गया, के मामले में इस न्यायालय की विद्वत खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय संदर्भित है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने, अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने वाले जाँच अधिकारी की गैर-जाँच के मुद्दे पर, मुन्ना लाल बनाम उतरप्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है। ***मुन्ना लाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य और उसके अनुरूप मामला,*** ए.आई.आर. 2023 एस.सी. 634, में रिपोर्ट किया गया पैराग्राफ सं. 28 और 42 जिनका पुनरुत्पादन यहां नीचे किया गया हैः-

> *"28. इन अपीलार्थियों के भाग्य का निर्णय करने की कवायद शुरू करने से पहले, इन दोनों अपीलों पर निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ सिद्धांतों पर ध्यान देना उचित होगा।यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सिद्धांत वर्षों से विकसित हुए हैं और 'कानून के स्थिर सिद्धांतों' में परिवर्तित हो गए हैं। ये हैंः(ए)।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 इस मान्यता प्रास उक्ति को स्थापित करती है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, यह सबूत की गुणवत्ता है जो मायने रखती है न कि मात्रा। एक उत्तराधिकारी के रूप में, हत्या के मामले में भी, गवाहों की बहुलता पर जोर देना आवश्यक नहीं है और एक गवाह का मौखिक साक्ष्य, यदि विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो दोषसिद्धि हो सकती है।(बी)।आम तौर पर, मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्।:(i) पूरी तरह से विश्वसनीय; (ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय; (iii) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय। मामलों की पहली दो श्रेणियां न्यायालय के लिए अपने निष्कर्षों पर*

पहुंचने में गंभीर कठिनाई पैदा नहीं कर सकती हैं।हालांकि, मामलों की तीसरी श्रेणी में, अदालत को सावधानी बरतनी होगी और विवेक के नियम की आवश्यकता के रूप में, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य विश्वसनीय गवाही द्वारा किसी भी भौतिक विवरण की पुष्टि की तलाश करनी होगी।(सी)।एक दोषपूर्ण जाँच हमेशा अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होती है जहाँ नेत्र संबंधी गवाही विश्वसनीय और ठोस पाई जाती है।जबकि ऐसे मामले में अदालत को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी होती है, सभी मामलों में एक दोषपूर्ण जांच एक विश्वसनीय अभियोजन संस्करण को खारिज करने के लिए एक निर्धारक कारक नहीं हो सकती है।(डी)।जाँच अधिकारी की गैर-जाँच के परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह होना चाहिए; यदि कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा होता है, तो केवल गैर-जाँच अभियोजन मामले को घातक नहीं बना देगी।(ई)।जब कोई गवाह कुछ समय बीतने के बाद स्वाभाविक तरीके से गवाही देता है, और यदि ऐसी विसंगतियां तुलनात्मक रूप से मामूली प्रकृति की होती हैं और अभियोजन पक्ष की कहानी की जड़ तक नहीं जाती हैं, तो उन्हें अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है।

42. हालांकि, जांच प्रक्रिया में केवल दोष ही बरी होने का आधार नहीं हो सकते हैं, प्रत्येक मामले में जांच अधिकारी के चूक के बावजूद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने का न्यायालय का कानूनी दायित्व है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य बिल्कुल भी विश्वसनीय है और क्या ऐसी खामियां सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य को

प्रभावित करती हैं।कानून में उपरोक्त स्थिति के प्रति सचेत होने और आपराधिक न्याय के प्रशासन में लोगों के विश्वास और आस्था के क्षरण से बचने के लिए, इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की जांच की है और जांच अधिकारी की लापरवाही के साथ-साथ उसके द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण जांच के परिणामस्वरूप चूक या चूक को प्रमुखता देने से परहेज किया है।इस न्यायालय का प्रयास रहा है कि अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करके मामले की जड़ तक पहुंचा जाए और यह पता लगाया जाए कि क्या अपीलार्थी विधिवत रूप से दोषी पाए गए थे और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषी कानून की कठोरता से न बचे। जांच की प्रक्रिया में परेशान करने वाली विशेषताओं पर, जब से ध्यान दिया गया है, अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देने के लिए अदालत के दिमाग में वजन नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के उचित मूल्यांकन पर, यह पता चला है कि ऐसे कारण थे जिनके लिए पीडब्लू-2/ अ.सा. 2 ने अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाया हो सकता है और यह भी कि पीडब्लू-3/ अ.सा.3 पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं था।अभियोजन पक्ष की कहानी में काफी हद तक अनिश्चितता है और ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे की अदालतें अन्य उपस्थित परिस्थितियों के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना पीडब्लू-2/ अ.सा/2 और पीडब्लू-3/ अ.सा.3 की मौखिक गवाही से कुछ हद तक प्रभावित हुई हैं, जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

8. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जो विवाद/झगड़ा/लड़ाई हुई थी, उसका कारण तुच्छ था, क्योंकि यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा तिरंगा *(गुटका)* को तोड़ने और मृतक द्वारा इसके लिए भुगतान करने के लिए कहने के कारण, अपीलार्थी ने मृतक (सूचना देने वाले के बड़े भाई) की हत्या कर दी थी, हालांकि यह समझ से परे है कि इस तरह के मामूली मुद्दे से किसी व्यक्ति की हत्या हुई होगी।यह कहा गया है कि इस घटना के वास्तविक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसके अलावा इस तथ्य के अलावा कि घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद नहीं किया गया है।यह तर्क दिया जाता है कि मुकदमे के दौरान अपीलार्थी की ओर से न तो किसी प्रकार का इरादा और न ही कथित घटना को प्रभावी बनाने का कोई मकसद साबित हुआ है। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना आंदोलन के कारण हुई थी और अपीलार्थी सहित अभियुक्त व्यक्ति मृतक की हत्या करने के लिए किसी भी पूर्व नियोजित दिमाग से घटना स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के प्रावधान को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि मृतक की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था।

9. *इसके विपरीत,* राज्य के लिए विद्वान अ. लोक अभियोजक, सुश्री शशि बाला वर्मा ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलेगा कि उनके साक्ष्य में कोई विसंगति नहीं है, उन्होंने लगातार गवाही दी है, विशेष रूप से पीडब्लू-3/अ.सा.3, पीडब्लू-6/अ.सा.6 और पीडब्लू-7/अ.सा.7, जो उक्त घटना के चश्मदीद गवाह हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है

कि पहले भी, पक्षों के बीच एक विवाद हुआ था जैसा कि पीडब्लू-6/अ.सा.6 के साक्ष्य से स्पष्ट है, जो पैराग्राफ सं. 9 अपने बयान में कहा गया है कि उसने पहले भी चने के लिए पैसे मांगे थे, हालांकि, आरोपी ने उस पर मुट्ठी से हमला किया था।पैराग्राफ सं. 37 का भी संदर्भ दिया गया है। पीडब्लू-6/अ.सा.6 के साक्ष्य में से यह प्रस्तुत करने के लिए कि उसने कहा है कि वर्तमान घटना की तारीख से दो दिन पहले, राकेश (अपीलार्थी) के साथ झगड़ा हुआ था, हालाँकि, मृतक के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था।राज्य के लिए विद्वान अ. लोकअभियोजक ने पैराग्राफ संख्या 40 का उल्लेख करके आगे प्रस्तुत किया है। पीडब्लू-6/अ.सा.6 के सबूतों में से कि अपीलार्थी ने उसके अपने बड़े भाई पर बार-बार खंजर से वार किया था।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.07.2012 के आदेश का उल्लेख करते हुए राज्य के लिए विद्वत एपीपी (अ. लोकअभियोजक) द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि डॉक्टर ने मूल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को साबित कर दिया है और रिकॉर्ड से यह पता चलेगा कि मूल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है।

10. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के अलावा, हमने साक्ष्य, यानी मौखिक और दस्तावेजी, दोनों का बारीकी से अध्ययन किया है।आगे बढ़ने से पहले, साक्ष्य पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करना आवश्यक होगा।

11. पीडब्लू-1/अ.सा.1 मोती चंद साह, पीडब्लू-2/अ.सा.2 दीन दयाल राम, पीडब्लू-4/अ.सा.4 हुलास राम, पीडब्लू-5/अ.सा.5 रुदल सिंह और पीडब्लू-8/अ.सा.8 धर्मनाथ मांझी को शत्रुतापूर्ण (पक्षद्रोही) घोषित किया गया है, इसलिए हमें उक्त गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता है, फिर भी हम यह बताना चाहेंगे कि जहां तक पीडब्लू-5/अ.सा.5

रुदल सिंह का संबंध है। उनकी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ 6 में कहा कि (बचाव पक्ष द्वारा की गई) कि जिस स्थान पर राम मंगल प्रसाद पर हमला किया गया था, उस समय उनके भाई सुरेंद्र प्रसाद साह (पीडब्लू-6/अ.सा.6) और उनके पिता सुदर्शन साह (पीडब्लू-3/अ.सा.3) वे मौजूद नहीं थे और एक घंटे के बाद आ गए थे।

12. पीडब्लू-3/अ.सा.3 सुदर्शन साह सूचना देने वाले के पिता हैं और मृतक के पिता भी हैं। पीडब्लू-3/अ.सा.3 ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना वर्ष 1995 में लगभग 06:00 बजे शाम की है और दिन शनिवार था। उन्होंने कहा है कि यह घटना 08.07.1995 को हुई थी। घटना के दिन पीडब्लू-3/अ.सा.3 का बेटा राम मंगल प्रसाद अपनी दुकान पर बैठा था और वह भी वहाँ मौजूद था। यह दुकान लकड़ी से बनी है। उक्त दुकान में पान (पान), किराना (किराने का सामान), तिरंगा (गुटका) आदि बेचे जाते थे। पीडब्लू-3/अ.सा.3 ने आगे कहा है कि उनके दूसरे बेटे का नाम सुरेंद्र प्रसाद साह है और वह तले हुए चना बेचता था।पीडब्लू-3/अ.सा.3 ने इसके बाद कहा कि आरोपी व्यक्ति राकेश सिंह (अपीलकर्ता), मनोज सिंह और अशोक सिंह दुकान पर आए थे और उन्होंने तिरंगा मांगा था जो उन्हें दिया गया था, जिसके बाद राकेश सिंह (अपीलकर्ता) ने खुद ही तिरंगे का एक थैला तोड़ लिया था और जब पैसे मांगे गए तो अशोक सिंह ने उसे दुकान से बाहर निकालने और उसे मारने का आह्वान किया था, जिसके बाद राकेश सिंह (अपीलकर्ता) और मनोज सिंह ने उसे दुकान से बाहर खींच लिया था, जिससे वह जमीन पर गिर गया और फिर राकेश सिंह (अपीलकर्ता) ने खंजर निकाला। और मृतक पर पहला खंजर मारा जो उसके दाहिने हाथ की उंगली में लगा।इसके बाद, राकेश सिंह ने मृतक की छाती पर दूसरा खंजर मारा

और खंजर घुमाया, जिसके बाद वह नीचे गिर गया और खून बहने लगा और उसकी तुरंत मौत हो गई, जबकि पीडब्लू-3/अ.सा.3 वहाँ खड़ा था।जहां तक कठघरे में खड़े आरोपी की पहचान का सवाल है, पीडब्लू-1/अ.सा.1 ने कहा था कि वह गवाहों को बहुत नजदीक दूरी से देखना चाहता है, जिसके बाद वह आरोपी व्यक्तियों के पास गया और मनोज सिंह और राकेश सिंह (अपीलार्थी) को पहचान लिया।अदालत द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि वह तीसरे आरोपी व्यक्ति को भी पहचान सकते हैं।

13. अपनी जिरह में पीडब्लू-3/अ.सा.3 ने कहा है कि पुलिस कोउन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कहा है कि घटना के समय, 25-30 संख्या में वाले कई व्यक्ति घटना स्थल पर पहुंचे थे और उनमें से वह केवल तीन व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं। पीडब्लू-3/अ.सा.3 ने आगे कहा है कि हालांकि 25-30 लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन वह यह नहीं कह सकते कि वे एक ही गाँव के थे या नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि घटना का स्थान गमरिया गाँव में स्थित है। इसके बाद उन्होंने कहा कि घटना के बाद गमहरिया गांव के कई लोग वहां पहुंचे, जिनमें पंचम साह, मोती चंद साह (पीडब्लू-1/अ.सा.1), दीन दयाल चमार और राम दयाल चौधरी (पीडब्लू-7/अ.सा.7) शामिल थे।उन्होंने कहा है कि वह अन्य व्यक्तियों के नाम नहीं बता सकते हैं, जो वहां पहुंचे थे।पैराग्राफ सं.11 अपनी जिरह के बारे में, पीडब्लू-3/ अ.सा.3 ने कहा है कि उसने पुलिस के सामने यह नहीं कहा है कि वर्तमान घटना से पहले उसके बेटे सुरेंद्र और राकेश (अपीलकर्ता) के बीच मुट्ठी के साथ झगड़ा (हाथापाई) हुआ था।उन्होंने आगे कहा है कि जिस जमीन पर दुकान स्थित है, वह राम दयाल चौधरी (पीडब्लू-7/ अ.सा.7) की है।पैराग्राफ सं.14 में उसकी जिरह के बारे में, पीडब्लू-3/ अ.सा.3 ने कहा है

कि 300-400 ग्रामीण घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने उनमें से किसी से भी बात नहीं की। पैराग्राफ सं.15 में उसकी जिरह के बारे में, पीडब्लू-3/ अ.सा.3 ने कहा है कि जब अभियुक्त व्यक्तियों ने राम मंगल को अपनी दुकान से बाहर खींचा था तो उसके बेटे सुरेंद्र (पीडब्लू-6/ अ.सा.6), धर्मनाथ राय (पीडब्लू-8/ अ.सा.8), चौकीदार, राम दयाल चौधरी (पीडब्लू-7/ अ.सा.7), दीन दयाल राम (पीडब्लू-2/ अ.सा.2) और हुलास राम (पीडब्लू-4/ अ.सा.4) सहित 2 से 4 लोग वहां मौजूद थे, हालांकि उस समय कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था।पैराग्राफ सं.16 उसकी जिरह के बारे में, पीडब्लू-3/ अ.सा.3 ने कहा है कि उसके बेटे पर दुकान के दक्षिणी हिस्से में लगभग एक हाथ की दूरी पर हमला किया गया था और जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वह राम मंगल के दक्षिणी हिस्से की ओर खड़ा था। उसने यह भी कहा है कि राम मंगल पर हमला किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया था।पैराग्राफ सं.17 उसकी प्रतिपरीक्षा के बारे में, पीडब्लू-3/ अ.सा.3 ने कहा है कि हमला किए जाने के बाद, उसका बेटा नीचे गिर गया था, जिसके बाद उस पर तीन बार हमला किया गया था और हमला किए जाने के समय, मृतक खड़ा नहीं था, बल्कि उसे खींचा गया और उस पर हमला किया गया।पैरा सं.19 उसकी जिरह के बारे में, पीडब्लू-3/ अ.सा.3 ने कहा है कि पुलिस रात में ही आई थी, हालाँकि उसे याद नहीं है कि वह वहाँ मौजूद था या नहीं।इसके बाद उन्होंने कहा कि घटना के बाद रात में पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था।

14. पीडब्लू-6/ अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह (सुचक) मृतक का भाई है और उसने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह घटना दिनांक 08.07.1995 के लगभग 06:00 बजे शाम की है जब वे अपने भाई राम मंगल प्रसाद के

साथ थे। साह उनकी पान की दुकान पर थे।राकेश सिंह (अपीलार्थी), मनोज सिंह और अशोक सिंह दुकान पर पहुंचे और एक तिरंगा गुटका तोड़ा, जिसके बाद उनके भाई राम मंगल ने पैसे मांगे थे, लेकिन अशोक सिंह ने उन्हें गाली दी और कहा कि वह पैसे कैसे मांग रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने दूसरों को उन्हें दुकान से बाहर निकालने और उन पर हमला करने के लिए उकसाया था। इसके बाद, मनोज सिंह और राकेश सिंह (अपीलकर्ता) ने राम मंगल को दुकान से बाहर निकाला था, जबकि राकेश सिंह ने अपनी पीठ से एक चाकू निकाला था, जिसके बाद मनोज सिंह ने राम मंगल के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और फिर राकेश सिंह ने राम मंगल की छाती पर चाकू मारा था और उसे अंदर डाल दिया था, साथ ही उसने राम मंगल की छाती पर दूसरा चाकू मारा था और उसे अंदर घुमाया था, जिसके बाद राम मंगल के हाथ पर तीसरा चाकू मारा गया था। पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने आगे कहा है कि उसका भाई खून से लथपथ था और नीचे गिर गया था और इस बीच चार व्यक्ति, राम दयाल चौधरी (पीडब्लू-7/ अ.सा.7), मचन साह, दीन दयाल राम (पीडब्लू-2/ अ.सा.2) और दिलीप कुमार वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उनके भाई, जो हिल रहे थे, की मृत्यु हो गई थी।अभियुक्त व्यक्तियों ने तब पीडब्लू-6/ अ.सा.6 का पीछा किया था, जब उसने शोर मचाया था, जिससे गाँव के 20-25 लोग वहाँ पहुँच गए थे जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त व्यक्ति भाग गए थे। पुलिस कर्मी तब आ गए थे और पीडब्लू-6/ अ.सा.6 का बयान दर्ज किया गया जिसे उसे पढ़ाया गया और उसे समझने के बाद, उसने उसी पर अपना हस्ताक्षर किया था जिसे उसने पहचाना है और उसे प्रदर्शनी-3 के रूप में चिह्नित किया गया है। पीडब्लू 6/ अ.सा.6 ने यह भी कहा है कि जब्त की गई खून से लथपथ मिट्टी और कपड़ों की

जब्ती सूची भी बनाई गई थी।पीडब्लू6/ अ.सा.6 ने कहा है कि उन्होंने अदालत में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दिया था, जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसे प्रदर्शनी-4 के रूप में चिह्नित किया गया है।पैरा सं.9 अपने बयान के बारे में, पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि पहले भी जब उसने चने के लिए पैसे की मांग की थी, तो उस पर मुट्ठी से हमला किया गया था।पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कटघरे में खड़े राकेश सिंह और मनोज सिंह को पहचान लिया था।

15. पैराग्राफ सं.13 उसकी जिरह के बारे में पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि घटना के बाद ग्रामीण पुलिस स्टेशन गए थे और गांव का चौकीदार भी पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन वह अपना नाम नहीं बता सकता।वह चौकीदार से नहीं मिला था और वह यह नहीं कह सकता था कि चौकीदार उसकी दुकान पर कब आया था, हालांकि उसने कहा है कि ग्रामीणों ने उसे बताया था कि चौकीदार पुलिस को सूचित करने गया था।पैराग्राफ सं.14 उसकी जिरह के बारे में, पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि घटना के बाद, वह पूरी रात चौकीदार से नहीं मिला था, हालांकि वह पूरी रात घटना स्थल पर और उसके साथ गमहरिया गाँव के 50-60 लोगों सहित कई लोग भी वहाँ मौजूद थे।उन्होंने कहा है कि उक्त व्यक्तियों में से वे चार ग्रामीणों राम दयाल चौधरी (पीडब्लू-7/ अ.सा.7), मोती चंद साह (पीडब्लू-2/ अ.सा.2), दीन दयाल राम और दिलीप कुमार चौधरी के नाम बता सकते हैं और इसके अलावा उनके पिता भी वहां मौजूद थे।उन्होंने यह भी कहा है कि प्रभारी अधिकारी 1:00-02:00 बजे रात में पहुंचे थे अन्य पुलिस कर्मियों के साथ और उस समय उनके गाँव से कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं आया था।पैराग्राफ नं.16 अपनी जिरह के बारे में, पीडब्लू-6/अ.सा.6 ने कहा है कि प्रभारी

अधिकारी ने उसका बयान सबसे पहले लगभग 02:00 बजे ए.एम. रात में दर्ज किया था। पैराग्राफ सं 26 अपनी जिरह के बारे में पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि वह दुकान में बिस्कुट और टॉफी के साथ साबुन, सर्फ, तिरंगा गुटका (जो दुकान में लटका हुआ था), पान (पान) बेचता था।उन्होंने यह भी कहा है कि दुकान के अंदर किसी भी वस्तु को बाधित नहीं किया गया था और दुकान को ध्वस्त नहीं किया गया था, हालांकि दुकान के सामान दक्षिण की ओर दुकान के बाहर बिखरे हुए थे।पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने अपनी जिरह में कहा है कि आरोपी व्यक्ति लगभग 10 मिनट तक उसकी दुकान पर रहे थे और जब वे आए थे, तो कोई ग्राहक वहां मौजूद नहीं था।

16. पैराग्राफ सं. 30 उसकी जिरह के बारे में, पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि जैसे ही आरोपी व्यक्ति दुकान पर पहुंचे, उन्होंने तिरंगे की थैली तोड़ दी थी और उसके भाई पर हमला होने के बाद वे वहां पांच मिनट तक रहे थे, इस दौरान चार लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने तब कहा था कि उक्त चार लोग पहले से ही वहां मौजूद थे।यह भी कहा गया है कि उक्त पाँच मिनट के दौरान, गाँव के कुल 50-60 लोग वहाँ पहुंचे थे, लेकिन वे उनका नाम नहीं बता सकते।पैराग्राफ सं .31 उसकी जिरह के बारे में, पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि जिस समय आरोपी व्यक्तियों ने तिरंगा तोड़ा था, वह दुकान के अंदर था और जब राम मंगल पर हमला किया गया था, वह दुकान के बाहर था।

17. पैराग्राफ सं.34 उसकी जिरह में, पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि राम मंगल के शरीर पर तीन चोटें थीं, जबकि दो चोटें छाती के बीच में थीं, तीसरी चोट दाहिने हाथ की कलाई पर थी।कलाई पर केवल एक चोट लगी

थी।उन्होंने यह भी कहा है कि उनके भाई ने जो कपड़ा पहना था, उस पर छाती के पास एक छेद हो गया था।इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके भाई ने शर्ट पहनी हुई थी जिसमें दो स्थानों पर छेद किया गया था।पैरा सं.36 उसकी प्रतिपरीक्षा के बारे में, पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि उसके भाई राम मंगल पर उस समय हमला किया गया था जब वह खड़ा था और जब उस पर हमला किया गया था, तो वह जमीन पर गिर गया था, हालांकि, उसके बाद उस पर हमला नहीं किया गया था।पैराग्राफ सं. 37 उनकी प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि वर्तमान घटना से दो दिन पहले उसके और राकेश सिंह (अपीलार्थी) के बीच झगड़ा हुआ था, हालांकि आरोपी व्यक्तियों और राम मंगल के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था।उन्होंने यह भी कहा है कि राम मंगल ने न तो किसी आरोपी व्यक्ति पर हमला किया था और न ही दुर्व्यवहार किया था। पैराग्राफ सं. 39 अपनी जिरह के बारे में पीडब्लू-6/ अ.सा.6 ने कहा है कि राम मंगल की पहले से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी।

18. पीडब्लू-7/ अ.सा.7 राम दयाल चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना 7-8 साल पुरानी है और यह घटना शाम को बाजार में उनके घर के पास हुई थी जब अंधेरा हो गया था।उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने देखा कि एक दुकानदार की हत्या कर दी गई थी।राकेश सिंह (अपीलार्थी) ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फिर वह भाग गया था। छाती में चाकू घुसा दिया था। राकेश सिंह ने मृतक पर हमला किया था, जिसके बाद वह भाग गया था। पीडब्लू-7/ अ.सा.7 जब उसे आरोपी की पहचान करने के लिए कहा गया, तो वह राकेश सिंह के पास गया और उसे पहचान लिया। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 14-15 वर्षों से उन्हें अपनी

दृष्टि में कठिनाई हो रही है।उसने कहा है कि घटना के समय, वह मृतक की दुकान से सटे दुकान पर चाय पी रहा था, जो बाजार में स्थित है।100 लोग वहाँ मौजूद थे लेकिन वे वहाँ उपस्थित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। पैराग्राफ सं.5 में उनके मुख्य परीक्षण में पीडब्लू-7/ अ.सा.7 ने कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि हत्या होने के बाद अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे थे या नहीं।उन्होंने यह भी कहा है कि घटना के समय मोती चंद साह (पीडब्लू-1/ अ.सा.1) वहां मौजूद थे, जो उनके साथ चाय पी रहे थे, हालांकि, मारे गए दुकानदार के परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था।

19. पीडब्लू-9/ अ.सा.9 डॉ. राम इकबाल प्रसाद डॉक्टर हैं, जिन्होंने मृतक राम मंगल प्रसाद के शव का पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया था।उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि 09.07.1995 को, उन्हें सदर अस्पताल, छपरा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और उस तारीख को, 1:15 दोपहर में, उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया था और उनके शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-पोस्टमार्टम चोटें पाई थीं:-

> *"(i) लगभग मध्य उरोस्थि क्षेत्र के ठीक नीचे एक छेदित भेदक घाव।2" x 1/2 "x छाती गुहा गहरी।*
>
> *(ii) लगभग दाहिनी ओर उरोस्थि के निचले हिस्से पर एक छेदित भेदक घाव।1"x 1/2 "x छाती गुहा गहरी।*
>
> *(iii) दाहिनी कलाई पर दो घाव, एक लगभग।" रेडियल स्टाइलॉइड के पास पार्श्व की ओर 1 x 1/2 "x 1/4"और दूसरा लगभग।11/2 "x 1/2" x 1/4 "लगभग।1" 1 वें के ऊपर।*

छाती गुहा के विच्छेदन पर पीडब्लू-9/अ.आ.9 के निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

"छाती का गुहा काले तरल रक्त से भरा हुआ था।दाहिने निलय में पंक्चर घाव था और जिससे बाएं निलय की लंबाई 1 "और चौड़ाई 1/4"हो गई थी। उरोस्थि को चोट सं. (i) की रेखा में काटा गया था।अन्य सभी विसरा अक्षत पाए गए।

20. पीडब्लू-9/अ.सा.9 ने राय दी है कि मृत्यु रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई है और उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अंग हृदय को चोट लगी है, जो धारदार काटने वाले हथियार के कारण हुई थी।पीडब्लू-9/अ.सा.9 ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की पहचान की है, जिसे उन्होंने अपने लिखित में बताया है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उसे प्रदर्शनी-5 के रूप में चिह्नित किया गया है।जिरह में, पीडब्लू-9/अ.सा.9 ने कहा है कि उसने मृतक के व्यक्ति के शरीर पर चार चोटें पाई थीं, जो चार प्रहारों के प्रभाव से थीं। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतक के बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी।

21. पीडब्लू-10/अ.सा.10 सुरेश कुमार एक अधिवक्ता क्लर्क हैं, जिन्होंने श्री गंगा सागर चौबे के लेखन और हस्ताक्षर की पहचान की है, जिन्हें 09.07.1995 को जलालपुर थाना में पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था।उन्होंने कहा है कि फरदबेयान उनके लेखन में है और उनके हस्ताक्षर हैं जिन्हें उन्होंने पहचाना है और इसे पहले प्रदर्शनी-3 के रूप में चिह्नित किया गया है।पीडब्लू-10/अ.सा.10 ने यह भी कहा है कि वह पुलिस के उप-निरीक्षक श्री बिशेश्वर प्रसाद के लेखन और हस्ताक्षर को

पहचानता है, जो 09.07.1995 को छपरा मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उन्होंने को बताया है कि औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन उनके लिखित रूप में है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं जिसकी उन्होंने पहचान की है और इसे प्रदर्शनी-6 के रूप में चिह्नित किया गया है।जिरह में, पीडब्लू-10/अ.सा.10 ने कहा है कि वह यह नहीं कह सकते कि क्या बिशेश्वर प्रसाद अभी भी नौकरी में हैं और क्या वह जीवित हैं या नहीं।पीडब्लू-10/अ.सा.10 ने कहा है कि उन्होंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था और वह हस्तलेख के विशेषज्ञ नहीं हैं।

22. पीडब्लू-11/अ.सा.11 श्रवण कुमार सिंह भी एक अधिवक्ता क्लर्क हैं और उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि 09.07.1995 को, जलालपुर थाना के प्रभारी अधिकारी एक गंगा सागर चौबे थे, जिनके लेखन और हस्ताक्षर को वे पहचानते हैं।उन्होंने आगे कहा है कि मृतक राम मंगल प्रसाद की अन्वीक्षा जांच रिपोर्ट पैराग्राफ सं. 2 में गंगा सागर चौबे के लेखन में केस-डायरी, जिसे प्रदर्शनी-6 (विरोध के साथ) के रूप में चिह्नित किया गया है। पीडब्लू 11/अ.सा.11 ने कहा है कि खून से लथपथ मिट्टी की जब्ती सूची, जिसका उल्लेख पैराग्राफ सं.6 में मामले की केस डायरी तत्कालीन प्रभारी अधिकारी गंगा सागर चौबे के लिखित में है और इसे प्रदर्शनी-7 (विरोध के साथ) के रूप में चिह्नित किया गया है।जिरह में, पीडब्लू-11/अ.सा.11 ने कहा है कि वह फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ नहीं हैं, उन्हें गंगा सागर चौबे के साथ काम करने का कोई अवसर नहीं मिला और दोनों प्रदर्शन उनके सामने तैयार नहीं किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि प्रदर्श के गवाह कौन थे। और किसने जब्ती सूची बनाया था। पीडब्लू-11/अ.सा.11 ने कहा है कि उक्त दस्तावेज उनके सामने तैयार नहीं किए गए थे।

23. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, विद्वत विचारणन्यायालय ने अपीलार्थी का बयान 17.12.2012 को दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया, ताकि वह अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से समझा सके, हालांकि उन्होंने कहा कि वह लिखित रूप में देंगे।

24. विचारण न्यायालय ने विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना, विश्लेषण और जांच पर, उपरोक्त अपीलार्थी को अपराध का दोषी पाया है और उसे कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा।

25. हमने विद्वत विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय, अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया है और अपीलार्थी के विद्वत वरिष्ठ वकील के साथ-साथ राज्य के विद्वत अ. लोकअभियोजक द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है।

26. पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उपरोक्त अपीलार्थी पर जिन अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है, उसके लिए उसके अपराध को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं।अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-3/अ.सा.3 सुदर्शन साह, पीडब्लू-6/अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह (सुचक) और पीडब्लू-7/अ.सा.7 राम दयाल चौधरी (स्वतंत्र गवाह), के साक्ष्य का नेतृत्व किया है। इसके अलावा पीडब्लू-9/अ.सा.9 डॉ. राम इकबाल प्रसाद, पीडब्लू-10/अ.सा.10 सुरेश कुमार और पीडब्लू-11/अ.सा.11 श्रवण कुमार सिंह के साक्ष्य से अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए और उसी के

आधार पर विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया है। जबकि इसके विपरीत, अपीलार्थी ने मुख्य रूप से बचाव पक्ष को लिया है कि गवाहों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास हैं, वर्तमान मामले के जांच अधिकारी की जांच नहीं की गई है जिससे बचाव पक्ष के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद नहीं किया गया है, केवल फोटो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति प्रदर्शित की गई है, इसलिए इसकी जांच नहीं की जा सकती है और इसके अलावा, कोई उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया है।इस संबंध में, पीडब्लू-3/अ.सा.3 सुदर्शन साह, पीडब्लू-6/अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह और पीडब्लू-7/अ.सा.7 राम दयाल चौधरी के साक्ष्य के अवलोकन पर, हम उनके साक्ष्य में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं पाते हैं।यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि साक्ष्य में मामूली चूक या भिन्नता या दुर्बलता को कभी भी घातक नहीं माना जाता है और यह पूरी तरह से साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है और यह गवाहों के गुणात्मक मात्रा की विश्वसनीयता को भी प्रभावित नहीं करता है क्योंकि चश्मदीद गवाहों की गवाही में मामूली विसंगतियां स्वाभाविक हैं, जबकि पूरी तरह से त्रुटिहीन गवाही ट्यूशन का संकेत दे सकती है। इस संबंध में रम्मी बनाम म.प्र. राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लिया जाना चाहिए। रम्मी बनाम म.प्र. राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 649 में सूचित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मास्टर और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मास्टर और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी. 324*** में सूचित, पैराग्राफ सं.15 जिसका पुनरुत्पादन यहां नीचे किया गया हैः-

*"**15.** मामले में जांचे गए गवाहों के साक्ष्य की सराहना करने से पहले, मौखिक साक्ष्य की सराहना के लिए मानदंडों का उल्लेख करना शिक्षाप्रद होगा।एक गवाह के साक्ष्य की सराहना करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसमें सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है।एक बार जब यह धारणा मिल जाती है, तो निस्संदेह अदालत के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की अधिक जांच करे, विशेष रूप से समग्र रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, त्रुटियों और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह साक्ष्य के सामान्य सार के खिलाफ है और क्या साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन इसे विश्वास के अयोग्य बनाने के लिए हिलाया गया है।मामूली मामलों पर मामूली विसंगतियाँ जो मामले के मूल को नहीं छूती हैं, साक्ष्य से यहाँ या वहाँ संदर्भ से निकाले गए वाक्यों को लेकर अति तकनीकी दृष्टिकोण, जांच अधिकारी द्वारा की गई कुछ तकनीकी त्रुटि को महत्व देना जो मामले की जड़ तक नहीं जाता है, सामान्य रूप से साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।"*

27. हम अभियोजन पक्ष की गवाही से भी पाते हैं। गवाह, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की गई है कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और बचाव पक्ष द्वारा उनकी जिरह में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया है, ताकि उनके साक्ष्य की सत्यता पर संदेह किया जा सके।वास्तव में, दोनों उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों, यानी पीडब्लू-3/अ.सा.3 सुदर्शन साह और पीडब्लू-6/अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह ने

निश्चित रूप से अपीलार्थी को मृतक की छाती पर और उसके हाथ पर भी खंजर/चाकू से वार करते देखा है, जबकि पीडब्लू-7/अ.सा.7 राम दयाल चौधरी (स्वतंत्र गवाह) ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने चाकू डालकर एक दुकानदार की हत्या की है। पीडब्लू-9/अ.सा.9 डॉ. राम इकबाल प्रसाद, जिन्होंने मृतक-राम मंगल प्रसाद के शव का पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया था, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम परीक्षण 9.7.1995 पर 1:15 बजे दोपहर में किया था जिसके बाद उन्होंने उरोस्थि के मध्य और निचले हिस्से में 2 "x 1/2"और 1 "x 1/2"के दो छेदे हुए घाव पाए थे, दोनों छाती गुहा के अलावा दाहिनी कलाई पर दो छेदे हुए घाव थे और उन्होंने राय दी है कि मृत्यु रक्तस्राव, सदमे और महत्वपूर्ण अंग हृदय में चोट के कारण हुई है, क्योंकि विच्छेदन पर उन्हें दाहिने निलय में पंक्चर घाव मिला है जो बाएं निलय की ओर जाता है, उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप, जो तेज काटने वाले हथियार से हुई हैं। इस प्रकार, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अभियोजन पक्ष के मामले का विवरण मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में नेत्र साक्ष्य (चश्मदीद गवाह) द्वारा पूरी तरह से समर्थित है, जो आगे चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई है और यह भी पुष्टि करता है कि मृतक को लगी चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए ***भागचंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 18 एस.सी.सी. 274*** में रिपोर्ट किया गया। ***सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य के मामले में, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 484*** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक चिकित्सा साक्ष्य कथित तरीके से होने वाली चोटों की सभी संभावनाओं

को पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं, तब तक चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम पाते हैं कि मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई अपरिवर्तनीय संघर्ष नहीं है जो अभियोजन मामले को खारिज करने की गारंटी देता है।

28. घटना स्थल के संबंध में, उपरोक्त अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों, जैसे पीडब्लू-3/अ.सा.3 सुदर्शन साह, पीडब्लू-6/अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह और पीडब्लू-7/अ.सा.7 राम दयाल चौधरी ने बयान दिया है कि यह मृतक/सुचक की दुकान है, यानी पीडब्लू-6/अ.सा.6 की।

29. अब अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए विवाद पर आते हैं। अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील ने इस आशय से कहा कि गवाहों, विशेष रूप से स्वतंत्र गवाह, अर्थात् पीडब्लू-7/अ.सा.7 राम दयाल चौधरी और पीडब्लू-6/अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास हैं, क्योंकि पीडब्लू-6/अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह ने कहा है कि घटना के समय, तार्केश्वर साह, दिलीप कुमार, राज किशोर और अशोक चौधरी द्वारा झगड़े को अलग किया गया था, हालांकि उक्त व्यक्तियों में से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए अभियोजन पक्ष ने मामले के वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों को दबाने के लिए जानबूझकर स्वतंत्र गवाहों को रोक दिया है। हम पाते हैं कि पीडब्लू-3/अ.सा.3 सुदर्शन साह, पीडब्लू-6/अ.सा.6 सुरेंद्र प्रसाद साह और पीडब्लू-7/अ.सा.7 राम दयाल चौधरी के नेत्र साक्ष्य (चश्मदीद गवाह) ठोस, तर्कसंगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं और साथ ही प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर भी खड़े हैं और पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण और चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप हैं, इसलिए कथित घटना में अपीलार्थी के

अपराध के बारे में कोई संदेह पैदा करने का कोई कारण नहीं है, जो सभी उचित संदेह से परे साबित होता है।यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि एक अदालत एकल चश्मदीद गवाह के आधार पर दोषी ठहरा सकती है यदि उसकी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के 134 के तहत अनिवार्य है जो यह प्रदान करता है कि किसी भी मामले में किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, साक्ष्य की गुणवत्ता, मात्रा से अधिक मायने रखती है। इस संबंध में अमर सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए। ***अमर सिंह बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली), (2020) 19 एस.सी.सी. 165*** में रिपोर्ट किया गया। यह समान रूप से एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से उत्पन्न नहीं होता है जिनके दूषित होने की संभावना है और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास कारण नहीं है, जैसे कि आरोपी के खिलाफ शत्रुता, उसे गलत तरीके से फंसाना चाहता है, जो कि यहां मामला नहीं है और इसके अलावा, आम तौर पर एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी की जांच करने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक पुराने उत्कृष्ट निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए। ***दालीप सिंह और अन्य का मामला बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364*** सूचित किया गया।

30. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस आशय के तर्क के संबंध में कि जाँच अधिकारी की गैर-जाँच अभियोजन पक्ष के मामले के लिए

घातक साबित हुई है और बचाव पक्ष के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है, हम पाते हैं कि अपीलार्थी अपने प्रति हुए पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने में विफल रहा है, इसलिए यह किसी भी तरह से अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है।यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि अभियोजन पक्ष के मामले को केवल जाँच अधिकारी, की जांच न होने के कारण विफल होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता बरकरार रहती है।इस संबंध में बिहारी प्रसाद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए। ***बिहारी प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1996) 2 एस. सी. सी. 317*** में सूचित किया गया।

31. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिया गया अगला तर्क यह है कि मुकदमे के दौरान प्रदर्शित दस्तावेज मूल होना चाहिए, जबकि वर्तमान मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी प्रदर्शित की गई है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है और उक्त प्रभाव के लिए ***सिद्धार्थ वशिष्ठ*** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है। हमारा विचार है कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क को केवल अस्वीकार किए जाने के उद्देश्य से नोट किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्वान निचली अदालत के रिकॉर्ड से पता चलेगा कि न केवल मूल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है, बल्कि यह पीडब्लू-9/अ.सा.9 डॉ. राम दयाल चौधरी द्वारा भी साबित किया गया है, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की पहचान की है और कहा है कि यह उनके लिखित में है और उनके हस्ताक्षर हैं। ***सिद्धार्थ वशिष्ठ*** (उपरोक्त) के मामले में अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से अलग है और वास्तव में है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा गलती से संदर्भित किया गया है, क्योंकि एक ही दस्तावेज़ के साथ संबंधित है जो एक विशेषज्ञ के हाथ में एक रिपोर्ट है, जैसा कि दंड प्रकिया संहिता की धारा 299 के तहत प्रदान किया गया है।

32. इस प्रकार, पूरे मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से उभरते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है और उन साक्ष्यों पर विचार करते हुए, जो अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर लाए गए हैं, साथ ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की भरोसेमंद और विश्वसनीयता पर विचार करते हुए, जिसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ प्रतिपरीक्षा के दौरान बदनाम नहीं किया गया है और ऊपर उल्लिखित कारणों से, हम पाते हैं कि हमारे दिमाग में कोई संदेह पैदा करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, कथित घटना में उपरोक्त अपील के अपीलार्थी के अपराध के बारे में कोई संदेह पैदा करने का कोई कारण नहीं है जो सभी उचित संदेहों से परे साबित होता है।इसलिए, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों की जांच करने के बाद, हम दोषसिद्धि के विवादित निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाते हैं।

33. अब हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस प्रभाव से उठाए गए वैकल्पिक तर्क पर विचार करेंगे कि घटना उस समय अचानक हुई थी और अपीलार्थी मृतक की हत्या करने के लिए किसी पूर्व नियोजित मन से घटना स्थल पर नहीं आया था, इसलिए वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि यह मृतक की मृत्यु

का कारण बनने के किसी भी इरादे के अभाव में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा।हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि न तो कोई गंभीर और अचानक उकसावा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी आत्म-नियंत्रण खो देता है और न ही यह ऐसा मामला है जहां यह कार्य इस जानकारी के बिना किया गया था कि यह मृत्यु का कारण बन सकता है, इस तथ्य के अलावा कि अपीलार्थी का निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बनने का इरादा था। हम यह भी पाते हैं कि भारतीय दंड संहिता धारा 300 का "अपवाद 4" भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, जो इस प्रकार हैः-

> *"अपवाद 4. आपराधिक मानव वध, हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जनित आवेश की तीव्रता में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया जाता है।"*

34. हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी, जो अपराधी है, चाकू से लैस था और उसने मृतक की छाती और हाथ पर बार-बार बेरहमी से हमला किया था, जबकि मृतक निहत्थे था, इसलिए अपराधी यानी अपीलार्थी ने निश्चित रूप से अनुचित लाभ उठाया है और क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया है। मृतक की ओर, जो सशस्त्र साबित नहीं हुआ है। इस संबंध में, बाबू और अन्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए। ***बाबू और अन्य बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और एक अन्य समान मामला, (2013)***

4 एस. सी. सी. 448, में रिपोर्ट किया गया। पैराग्राफ सं. 19 से 21 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

> ***"19.*** *हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील के निवेदन से भी आश्वस्त नहीं हैं कि यह एक ऐसा मामला था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को नीचे उद्धृत किया गया हैः*
>
> > *"अपवाद 4. आपराधिक मानव वध, हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जनित आवेश की तीव्रता में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया जाता है।*
>
> *इस प्रकार, धारा 4 से धारा 300 के अपवाद की भाषा स्पष्ट है कि गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं है, यदि इसे अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना किया जाता है, बशर्ते कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या क्रूरता या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया हो।इस मामले में, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृतक किसी भी तरह से सशस्त्र था जब उसने ए-1 से सवाल किया कि उसने अपनी पत्नी को क्यों धमकी दी थी।दूसरी ओर, अपीलकर्ता चाकू से लैस थे और मृतक के गिरने के बाद भी उनके सिर और चेहरे पर हमला किया। इस प्रकार, ए-1, ए-2, ए-3 और ए-4, जो अपराधी थे, ने अनुचित*

लाभ उठाया है और मृतक के प्रति क्रूर और असामान्य तरीका में कार्रवाई की है। जो सशस्त्र साबित नहीं हुआ है।

20. *इसके अलावा, हम पीडब्लू-7/अ.सा.7 के साक्ष्य से पाते हैं, डॉक्टर जिन्होंने मृतक का पोस्टमॉर्टम दिनांक 26.01.2004 को लगभग 12:45 बजे किया था, उन्होंने मृतक के सिर और चेहरे पर छह घाव पाए। इन चोटों को नीचे निकाला गया है:*

> *"चोट 1: बाएं गाल पर 3x2 सेमी और नाक की नोक पर 2x2 सेमी मापने वाले लाल रंग की चोट।*
>
> *चोट 2: निचले जबड़े पर 3x 0.05 सेमी गहरी हड्डी में एक तिरछी चीरा लगी चोट।*
>
> *चोट 3: एक चीरा लगी चोट ऊर्ध्वाधर, निचले जबड़े के बाईं ओर चौथा पर 2x 0.5 सेमी गहरी हड्डी में।*
>
> *चोट 4: एक छिद्रित चोट, इसकी दाहिनी ओर निचले होंठ पर गहरी 3x05 सेमी तिरछी मांसपेशी।*
>
> *चोट 5: कई चीरेदार चोटें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हैं।इसे खोलने पर, यह पाया गया कि कपाल पर ऊतक चोटिल पाए गए थे और खोपड़ी की हड्डियां टूट गई थीं और मस्तिष्क टूट गया था और बाहर से दिखाई दे रहा था।*
>
> *चोट 6: क्षैतिज रूप से देखी गई और आंखों के बीच में 22x6 सेमी की चोट लगी हुई है। विच्छेदन करने पर, यह पाया गया कि सभी ऊतकों, नसों और रक्त वाहिकाओं को*

काट दिया गया था, चेहरा टूट गया था और ऊपरी जबड़े की हड्डी और निचले जबड़े की हड्डी टूट गई थी।दोनों आंखें पूरी तरह से टूट गई थीं और आंखों के बाहर दिखाई दे रही थीं। ऊपरी जबड़े में और निचला जबड़ा में के दांत टूट गया और कुछ गिर गए थे।

पीडब्लू-7/अ.सा.7 ने आगे कहा है कि उसके सिर और चेहरे पर लगी इन चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो गई होगी जैसा कि उसने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.7 में व्यक्त किया है।चोटों की प्रकृति और विशेष रूप से, चोट संख्या 5 और 6 को ध्यान में रखते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ए-1, ए-2, ए-3 और ए-4 का सामान्य इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।तदनुसार, ए-1, ए-2, ए-3 और ए-4 (अपीलार्थी) भारतीय दंड संहिता धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराधों के दोषी थे।

21. *परिणामस्वरूप, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार हम उन्हें खारिज कर देते हैं।"*

35. हम भगवान मुंजाजी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य फैसले का भी उल्लेख करना चाहेंगे। ***भगवान मुंजाजी पावडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978) 3 एस. सी. सी. 330*** में रिपोर्ट किया गया। पैराग्राफ संख्या 6 और 7 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

*"**6.** हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय की इस छिटपुट टिप्पणी से बहुत कुछ कहा जा सकता है कि "अपीलार्थी ने अपने निजी*

बचाव के अधिकार को कहीं अधिक पार कर लिया था।"मामले की परिस्थितियों से पता चलता है कि निजी बचाव का कोई अधिकार, व्यक्ति या संपत्ति का, कभी भी अपीलार्थी को अर्जित नहीं हुआ था। मृतक निहत्थे थे। अपवाद 2 का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। यह सच है कि धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता के लिए कुछ शर्तें यहां मौजूद हैं, लेकिन सभी नहीं।झगड़ा अचानक शुरू हो गया था, लेकिन मृतक और अपीलार्थी के बीच अचानक कोई लड़ाई नहीं हुई। ''लड़ाई' एक द्वैपाक्षिक लेन-देन का प्रतिपादन करता है जिसमें प्रहारों का आदान-प्रदान किया जाता है।मृतक निहत्थे थे। उसने अपीलार्थी या उसके साथियों को कोई चोट नहीं पहुँचाई।इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा कुल्हाड़ी से कम से कम तीन घातक चोटें पहुंचाई गईं, जो निहत्थे पीड़ित पर एक दुर्जेय हथियार है।इसलिए, अपीलार्थी भी अपवाद 4 के लाभ का हकदार नहीं है।

***7.** इसलिए, हम सोचते हैं कि उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।इस तथ्य को कि अपराध पूर्व नियोजित नहीं था, सजा को कम करने में ध्यान में रखा गया है। हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं।"*

36. कुन्हीमहमद उर्फ कुन्हीथू के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक और फैसले का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। ***कुन्हीमहमद उर्फ कुन्हीथू बनाम केरल राज्य, 2024 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी***

3618, में रिपोर्ट किया गया। पैराग्राफ संख्या 6, 8, 25.8, 25.9, 25.16, 25.17, 25.18 और 30 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

> *"**6.** हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निखिल गोयल और केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. वी. दिनेश को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।श्री गोयल की दलीलें इस हद तक सीमित हैं कि यह पूर्व नियोजित हत्या का मामला नहीं था।हत्या के समान गैर इरादतन हत्या करने के लिए कोई दुराशय नहीं था।इरादा केवल छड़ी से हमला करने का था, लेकिन बाद में लड़ाई के दौरान मृतक ने अपीलार्थी को कुचल दिया और उसे पर हमला करना शुरू कर दिया। अपीलार्थी से छीनने के बाद उसी छड़ी से, अपीलार्थी ने उसकी पीठ से चाकू निकाला और उसे बचाने के लिए मृतक और घायल को भी चाकू मार दिया।उन्होंने अभिलेख पर साक्ष्य के साथ-साथ विचारण न्यायालय के निर्णय की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है जिसमें विशिष्ट निष्कर्ष विचारण न्यायालय द्वारा उस हद तक दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के बजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए आगे बढ़े।*
>
> ***8.** दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. वी. दिनेश ने कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने मामले के इस पहलू पर विचार किया है और साथ ही पाया है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला था। यह तथ्य कि अपीलार्थी*

के पास चाकू था और मृतक पर उसके द्वारा किए गए हमलों की संख्या और चोट भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इरादा हत्या करने का था।

25.8. *अपीलार्थी का प्राथमिक बचाव में हत्या करने के इरादे का अभाव रहा है।हालांकि, आशय का अनुमान कार्यवाही के आसपास की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है, जिसमें चोटों की प्रकृति और स्थान, उपयोग किया गया हथियार और घटना के दौरान अपीलार्थी की कार्रवाई शामिल है।चोटें मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों, जैसे छाती और पसलियों पर केंद्रित थीं, जिनमें हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं।इन क्षेत्रों को जानबूझकर निशाना बनाना नुकसान पहुँचाने के स्पष्ट इरादे का संकेत देता है जिससे मृत्यु हो सकती है। घायल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के अनुसार, अपीलार्थी ने मृतक को काफी बल से चाकू मार दिया, आगे अभियोजन पक्ष के इस तर्क की पुष्टि करते हुए कि चोटें जानबूझकर या कम से कम उनके प्राकृतिक परिणाम की जानकारी के साथ लगाई गई थीं। जबकि अन्य सह-अभियुक्त कथित तौर पर डंडों से लैस थे, अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 के पास एक नुकीला चाकू था, जिसका उपयोग गंभीर चोटों के लिए किया गया था। हाथापाई के दौरान इस तरह के हथियार को ले जाने और उपयोग करने का निर्णय केवल शारीरिक विवाद से परे हिंसा को बढ़ाने की तैयारी को दर्शाता है।भले ही अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का पूर्व इरादा नहीं था, परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि ऐसी चोटें लगी थीं जो सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।शरीर के*

महत्वपूर्ण भागों पर जानबूझकर छुरा घोंपने का कार्य, उपयोग किए गए बल के साथ, इंगित करता है कि अपीलार्थी को अपने कार्यों के संभावित घातक परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रावधानों के तहत, ऐसी चोटों का कारण बनने का इरादा जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं, हत्या के रूप में योग्य है, और भले ही हत्या का कारण बनने के इरादे के अलावा अन्य तत्व साबित हो जाएं, घातक कार्यों के परिणाम का केवल ज्ञान आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

25.9. *निचली अदालतों ने अपीलार्थी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि यह कार्य पूर्व नियोजित नहीं था।हालांकि हमले की योजना पहले से नहीं बनाई गई होगी, लेकिन पल की गर्मी में इरादा उभर सकता है, विशेष रूप से एक हिंसक टकराव के दौरान। घातक हथियार का उपयोग करने का अपीलार्थी का निर्णय और पीड़ित के महत्वपूर्ण अंगों को सटीक रूप से निशाना बनाना हत्या के लिए आवश्यक इरादे को स्थापित करने या कम से कम किसी के कार्यों के संभावित परिणामों की जानकारी और भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 3 के अनुसार मृतक की मृत्यु के लिए अपीलार्थी उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त है।*

25.16. *भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का तीसरा खंड हत्या को ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाकर मृत्यु का कारण बनने के कार्य के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप प्रकृति के*

सामान्य अनुक्रम में मृत्यु होने की संभावना है।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के कार्य इन मानदंडों को पूरा करते हैं। अपीलार्थी एक चाकू से लैस था, जिसका उपयोग वह महत्वपूर्ण अंगों पर कई चोटों के लिए करता था।इन चोटों की घातक प्रकृति, जैसा कि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई है, और हमले की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण बनने के इरादे या कम से कम इस ज्ञान के साथ चोट पहुँचाने के इरादे की ओर इशारा करती हैं कि उनके परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना थी।भले ही यह माना जाता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 का इरादा इस तरह की शारीरिक चोट पहुँचाने का नहीं था, महत्वपूर्ण भागों पर चाकू से चोट पहुँचाने का कार्य इस ज्ञान को दर्शाता है कि इस तरह की चोट पहुँचाने से सामान्य रूप से मृत्यु होने की संभावना है।

***25.17**.बचाव पक्ष का यह तर्क कि घटना एक सहज हाथापाई थी, अपीलार्थी को दायित्व से मुक्त नहीं करता है।हालांकि हाथापाई ने हमले को जन्म दिया हो सकता है, अपीलार्थी द्वारा घातक हथियार का उपयोग और जिस तरह से चोटें लगाई गईं, वह इस कृत्य को गैर-इरादतन हत्या से हत्या में बदल देता है।अदालतों ने लगातार यह माना है कि इरादे का अनुमान चोटों की प्रकृति और गंभीरता के साथ-साथ हथियार के चयन और इसके उपयोग के तरीके से लगाया जा सकता है।एक घातक हथियार का उपयोग और शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को जानबूझकर निशाना बनाना इस तरह के इरादे के मजबूत संकेतक हैं।*

25.18*. साक्ष्य और इसमें शामिल कानूनी सिद्धांतों के आलोक में, सहजता और पूर्वधारणा की कमी के आधार पर नरमी के लिए अपीलार्थी की याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता है।चोटों की प्रकृति और स्थान, हथियार का चयन, और हमले की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से सुब्रमण्यन की मृत्यु के लिए अपीलार्थी के दायित्व को स्थापित करती हैं।यह तर्क कि कार्य पल भर में किया गया था, अपराध की गंभीरता या अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कम नहीं करता है।*

30. *अपीलार्थी की दलीलों और मामले में प्रस्तुत साक्ष्य की पूरी तरह से जांच करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील और सजा में कमी का अनुरोध आधारहीन है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के निष्कर्ष अच्छी तरह से स्थापित हैं और प्रबल साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं।"*

37. इस मोड़ पर हम सिंगापागु अंजैया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले का भी उल्लेख करना चाहेंगे। ***सिंगापागु अंजैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 799,*** में रिपोर्ट किया गया। पैराग्राफ सं. 16 से 20 जिनका पुनरुत्पादन यहां नीचे किया गया हैः-

*"**16.** हमारी राय में, चूंकि कोई भी अभियुक्त के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए उसका इरादा इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोटों की*

प्रकृति से एकत्र किया जाना चाहिए।यहाँ, अपीलार्थी ने अपराध के हथियार के रूप में एक कील-उच्छेदक लौह दंड को चुना था। उन्होंने आगे शरीर के एक महत्वपूर्ण भाग यानी सिर को चुना है। चोट लगना जिससे खोपड़ी में कई फ्रैक्चर (अस्थिभंग) हो गए थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी ने किस बल से हथियार का इस्तेमाल किया था।इन सभी कारकों का संचयी प्रभाव अपरिहार्य रूप से एक और एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अपीलार्थी का इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।

17. *अब गुरमैल सिंह [(1982) 3 एस. सी. सी. 185 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए:1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 680], यही स्पष्ट रूप से अलग है।उक्त मामले में, तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि अभियुक्त का इरादा चोट पहुँचाने का नहीं था जो वास्तव में पाया गया था और उक्त पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि अभियुक्त का इरादा मृत्यु पहुँचाने का नहीं था, जो कि यहाँ स्थिति नहीं है।*

18. *जगतर सिंह [(1983) 2 एस. सी. सी. 342:1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 459] घटना से पहले अचानक और संयोग से झगड़ा हुआ था और उस पृष्ठभूमि में, अदालत ने माना कि आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत साबित हुआ। गुरमुख सिंह [(2009) 15 एस. सी. सी. 635:(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 711] मृतक पर पाई गई चोट केवल खोपड़ी की हड्डी का अवसाद था और यह घटना पल भर में*

हुई थी। उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, एक भी लाठी-प्रहार मृतक की मौत का कारण बनने के आरोपी के इरादे का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया।यहाँ, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऊपर बताए गए तीन महत्वपूर्ण कारक स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं कि अपीलार्थी का इरादा मृत्यु का कारण बनना था।

***19.** इसलिए, ये सभी निर्णय स्पष्ट रूप से अलग हैं।*

***20.** वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हथियार उपयोग किया गया, हमले के लिए चुने गए शरीर का हिस्सा और जिस तीव्रता के साथ अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसका इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।"*

38. अनबाझगन बनाम राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ***अनबाझगन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 857,*** में रिपोर्ट किया गया। पैराग्राफ सं. 66 जिसका पुनरुत्पादन यहां नीचे किया गया हैः-

*"**66.** उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट होने वाले कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः—*

(1) जब अदालत से इस सवाल का सामना किया जाता है कि आरोपी ने क्या अपराध किया है, तो सही परीक्षा यह पता लगाना है कि आरोपी ने क्या किया है।यदि इरादा या जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) से

(4) में वर्णित है, तो यह कार्य हत्या होगी, भले ही केवल एक चोट लगी हो।इसे स्पष्ट करने के लिएः'ए 'हाथ और पैर से बंधा होता है।'बी 'आता है और अपनी रिवॉल्वर को'ए 'के सिर पर रखता है, उसके सिर में'ए 'गोली मारता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है।यहां यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि 'ए'की गोली मारने में 'बी'का इरादा उसे मारने का था, हालांकि केवल एक चोट लगी थी।अतः यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) के अंतर्गत आने वाली हत्या का होगा। एक अन्य उदाहरण लेते हुए, 'बी'अपने दुश्मन 'ए'के शयनकक्ष में घुस जाता है जबकि बाद वाला अपने बिस्तर पर सो रहा है।'ए'की बाईं छाती पर निशाना साधते हुए, 'बी'जबरन 'ए'की बाईं छाती में तलवार घुसा देता है और भाग जाता है। 'इसके तुरंत बाद ए 'की मृत्यु हो जाती है। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में 'ए'की चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई गई।यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि 'बी'ने जानबूझकर विशेष चोट को जन्म दिया और यह कि उक्त चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए निष्पक्ष रूप से पर्याप्त थी।यह 'बी'के कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (3) के भीतर लाएगा और उसे हत्या के अपराध का दोषी ठहराएगा, हालांकि केवल एक चोट लगी थी।

(2) यहां तक कि जब अभियुक्त का इरादा या जानकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) से (4) के भीतर आ सकती है, तब भी अभियुक्त का कार्य जो अन्यथा हत्या होगी, हत्या के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, यदि अभियुक्त का मामला उस धारा में उल्लिखित पांच अपवादों में से किसी एक को आकर्षित करता है।उन अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने वाले मामले की स्थिति में, अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 की भाग 1 के अंतर्गत आने वाली गैर इरादतन हत्या होगी, यदि अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) से (3) के भीतर आता है। तो यह धारा 304 के भाग II के तहत अपराध होगा। यदि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (4) के अंतर्गत आता है तो यह धारा 304 के भाग 2 के तहत अपराध होगा। पुनः, अभियुक्त का इरादा या जानकारी ऐसी हो सकती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 का केवल दूसरा या तीसरा भाग आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के किसी भी खंड को नहीं। उस स्थिति में भी, अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या होगी। यह उस धारा के भाग I के तहत एक अपराध होगा, यदि मामला धारा 299 के दूसरे भाग के भीतर आता है, जबकि यह धारा 304 के भाग II के तहत

एक अपराध होगा यदि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तीसरे भाग के भीतर आता है।

(3) दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में वर्णित गैर इरादतन हत्या के मामलों के पहले दो खंडों के भीतर आता है, तो यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। हालाँकि, यदि यह तीसरे खंड के भीतर आता है, तो यह धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।वास्तव में, इसलिए, इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब 'दोषी इरादा'हो, जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा नहीं हो, लेकिन 'दोषी ज्ञान'हो।

(4) भले ही एक चोट लगी हो, अगर उस विशेष चोट का इरादा था, और निष्पक्ष रूप से वह चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 3 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और अपराध हत्या होगी।

(5) भारतीय दंड संहिता की धारा 304 निम्नलिखित वर्गों के मामलों पर लागू होगीः(i) जब मामला धारा 300 के खंडों में से एक या दूसरे के तहत आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादों में से एक द्वारा आवृत किया जाता है, (ii) जब होने वाली चोट संभावना की उच्च डिग्री की नहीं होती

है जो 'पर्याप्त'अभिव्यक्ति द्वारा आवृत की जाती है। प्रकृति का सामान्य अनुक्रम मृत्यु का कारण बनता है लेकिन इसकी संभावना कम होती है जिसे आम तौर पर 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना'वाली चोट के रूप में कहा जाता है और मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (2) के तहत नहीं आता है, (iii) जब यह कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि मृत्यु होने की संभावना है लेकिन मृत्यु या मृत्यु का कारण बनने की संभावना वाली चोट के इरादे के बिना किया जाता है।

इसे और अधिक संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दो भागों के बीच अंतर यह है कि पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है। इसलिए, किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के उद्देश्य से, अभियुक्त को अपने मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है।

(6) 'संभावना'शब्द का अर्थ है संभवतः और यह अधिक 'संभवतः'से अलग है।जब ऐसा होने की संभावना समान या

उससे अधिक होती है जो ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बात 'शायद होगी'। निष्कर्ष पर पहुँचने में, अदालत को खुद को अभियुक्त की स्थिति में रखना होता है और फिर यह निर्णय करना होता है कि क्या अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि इस कार्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।

(7) मामले से निपटते समय गैर इरादतन हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 299) और हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 300) के बीच के अंतर को हमेशा सावधानीपूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप के साथ मामले को निबटते समय। गैरकानूनी हत्याओं की श्रेणी के तहत, दोनों, गैर-इरादतन हत्या के मामले और गैर-इरादतन हत्या के मामले में आते हैं। जब मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पांच अपवादों के भीतर लाया जाता है तो दोषपूर्ण हत्या हत्या नहीं है। लेकिन, भले ही उक्त पांच अपवादों में से किसी का भी अनुरोध नहीं किया गया है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी हत्या के आरोप को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी के तहत मामले को लाने के लिए कानून के तहत अभियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक को स्थापित करने में इस

दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, अर्थात्, 1 से 4 तक, तो हत्या का आरोप नहीं लगाया जाएगा और मामला गैर-इरादतन हत्या का हो सकता है जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत वर्णित है।

(8) न्यायालय को दुराशय के प्रश्न पर स्वयं को संबोधित करना चाहिए।यदि धारा 300 का तीसरा खंड लागू किया जाना है, तो हमलावर को मृतक को दी गई विशेष चोट का इरादा रखना चाहिए।इस घटक को शायद ही कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित किया जा सकता है।अनिवार्य रूप से, यह मामले की सिद्ध परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है। अदालत को आवश्यक रूप से उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, शरीर के घायल हिस्से, चोट की सीमा, चोट पहुँचाने में उपयोग किए गए बल की मात्रा, हमले के तरीके, हमले से पहले की परिस्थितियों और परिचर को ध्यान में रखना चाहिए।

(9) हत्या का इरादा ही एकमात्र इरादा नहीं है जो एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है। प्रकृति के सामान्य कारण में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोट या चोट पहुँचाने का इरादा भी एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है यदि मृत्यु वास्तव में हुई है और ऐसी चोट या चोटें पहुँचाने के इरादे का अनुमान उस कार्य या कार्यों से

लगाया जाना है जिसके परिणामस्वरूप चोट या चोटें लगी है।

(10) जब अभियुक्त द्वारा की गई एकल चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का इरादा मृत्यु या उस विशेष चोट का कारण बनने का नहीं था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई।किसी अभियुक्त का दोषी ठहराने का इरादा था या नहीं, यह तथ्य का सवाल है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है।

(11) जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि अभियुक्त का इरादा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक चोट पहुँचाने का था और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में अपेक्षित चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तो, भले ही वह एक भी चोट लगाता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, अपराध पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तीसरे खंड के तहत आता है जब तक कि एक अपवाद लागू नहीं होता है।

(12) सवाल का निर्धारण करने में, क्या किसी आरोपी को उस मामले में दोषी इरादे या दोषी ज्ञान था जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट लगी है और वह चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तथ्य

यह है कि यह कार्य अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया जाता है, या कि परिस्थितियां यह औचित्य सिद्ध करती हैं कि चोट आकस्मिक अथवा अनजाने में लगी थी अथवा यह मात्र एक साधारण चोट थी, इससे दोषी ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है और अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अन्तर्गत होगा।"

39. ***अनबाझगन*** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को देखने के साथ-साथ पूर्ववर्ती पैराग्राफ में ऊपर निर्दिष्ट अन्य मामलों में भी और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को देखने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य, जो मृतक की मृत्यु का कारण बना है, न केवल इस ज्ञान के साथ था कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, बल्कि अपीलार्थी का इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनने का भी था क्योंकि उसने मृतक के महत्वपूर्ण हिस्से पर बार-बार प्रहार किया था, अर्थात। छाती के बीच में एक तेज काटने वाले हथियार यानी चाकू/खंजर से इस तरह से कि वह दिल में घुस गया था।“"आशय"और "ज्ञान" भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तत्व हैं और जहाँ तक किसी अभियुक्त द्वारा किया गया कोई कार्य, जो मृत्यु का कारण बनता है, इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि मृत्यु इस तरह के कार्य के कारण होने की संभावना है और अभियुक्त का भी मृत्यु का कारण बनने का इरादा था, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के दायरे में आएगा और अभियुक्त का ऐसा कार्य हत्या होगी।वर्तमान मामले में, चोटें मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर केंद्रित थीं। जैसे छाती और दिल।इन क्षेत्रों को जानबूझकर निशाना बनाना नुकसान पहुँचाने के स्पष्ट इरादे का संकेत देता है

जिससे मृत्यु हो सकती है।मान लीजिए, अपीलार्थी ने मृतक को काफी बल से चाकू मारा था, इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कि चोटें जानबूझकर या कम से कम उनके प्राकृतिक परिणाम की जानकारी के साथ लगाई गई थीं।अपीलार्थी के पास एक चाकू/खंजर था, जिसका उपयोग गंभीर चोट पहुँचाने के लिए किया जाता था।हाथापाई के दौरान इस तरह के हथियार को ले जाने और उपयोग करने का निर्णय केवल शारीरिक विवाद से परे हिंसा को बढ़ाने की तैयारी को दर्शाता है। भले ही अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का पूर्व इरादा नहीं था, परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि ऐसी चोटें लगी थीं जो सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।शरीर के महत्वपूर्ण भागों पर जानबूझकर छुरा घोंपने का कार्य, दुबारा उपयोग किए गए बल के साथ, इंगित करता है कि अपीलार्थी को अपने कार्यों के संभावित घातक परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रावधानों के तहत, ऐसी चोटों का कारण बनने का इरादा जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हैं, हत्या के रूप में योग्य है, और भले ही हत्या का कारण बनने के इरादे के अलावा अन्य तत्व साबित हो जाएं, केवल घातक कार्यों के परिणाम का ज्ञान आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

40. इस प्रकार, घातक हथियार का उपयोग करने का अपीलार्थी का निर्णय और मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को सटीक रूप से निशाना बनाना हत्या के लिए आवश्यक इरादे या कम से कम किसी के कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में जानकारी स्थापित करने और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 3 के अनुसार मृतक की मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी का यह तर्क कि घटना

एक स्वतःस्फूर्त हाथापाई थी, उसे उसके दायित्व से मुक्त नहीं करता है। हालांकि हाथापाई ने हमले को जन्म दिया हो सकता है, अपीलार्थी द्वारा घातक हथियार का उपयोग और जिस तरह से चोटें लगाई गईं, वह इस कृत्य को गैर-इरादतन हत्या से हत्या में बदल देता है।अदालतों ने लगातार यह माना है कि इरादे का अनुमान चोटों की प्रकृति और गंभीरता के साथ-साथ हथियार के चयन और इसके उपयोग के तरीके से लगाया जा सकता है। एक घातक हथियार का उपयोग और शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को जानबूझकर निशाना बनाना इस तरह के इरादे के मजबूत संकेतक हैं। नतीजतन, चूंकि अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में उल्लिखित पांच अपवादों में से किसी एक को आकर्षित नहीं करेगा, इसलिए वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के दायरे में नहीं आएगा।

41. मामले के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य से, तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित कारणों से, हम वर्तमान अपील, अर्थात् आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1215/2016 में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

सोनी श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

(सोनी श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।